नईदुनिया



सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली

गुरुनानक जयंती के मौके पर घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रह है। वहीं चांदी की कीमत में शुरुआती कारोबार के दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमत में तेजी आने के कारण देश के अलग अलग सर्राफा बाजार में शुद्ध सोना (24 कैरेट) और जेवराती सोना (22 कैरेट) 1,370 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है।

भाव में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,26,570 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,26,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,16,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,16,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी सोमवार के भाव यानी 1,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,26,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,16,160 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,26,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,16,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,26,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,16,060 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,26,570 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,16,010 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,26,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,16,010 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,16,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,26,720 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,16,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,16,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,16,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,26,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,16,160 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,26,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

न्यूज ब्रीफ

आरबीआई बैठक से पहले कंपनियों की फंड रेसिंग, 25,000 करोड़ जुटाने की तैयारी



नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक से पहले देश की कंपनियां सक्रिय हो गई हैं। करीब 25,000 करोड़ रुपए बान्ड जारी कर जुटाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी से पहले मौजूदा कम लागत पर लंबी अवधि का कर्ज सुरक्षित करना है। एमपीसी की बैठक 2 से 4 दिसंबर तक होनी है। रायटर्स के सर्वे और बाजार विश्लेषकों के अनुसार आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे पहले आरबीआई ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट को 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.50 फीसदी कर दिया था और अपनी नीति का रुख कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया था, जिसका अर्थ है महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर आगे भी दरें बढ़ाने की संभावना। इस संभावित बढ़ोतरी से बचने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया (एसआईडीबीआई), जियो क्रेडिट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और टोरेंट पावर जैसी सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां बान्ड के जरिए पैसा जुटाने में लगी हैं। नवंबर में-एएए रेटिंग वाले कारपोरेट बान्ड की यील्ड में 0.20 फीसदी से 0.30 फीसदी तक की गिरावट आई है, जिसे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, विदेशी निवेशकों की वापसी और रुपए की स्थिरता जैसे कारकों का समर्थन मिला है। इसी मौके का लाभ उठाकर कंपनियां अपनी उधारी लागत को नियंत्रित रखना चाहती हैं।

दिसंबर के पहले सप्ताह में बाजार में दस्तक देंगे दो आईपीओ



नई दिल्ली। भारतीय पूंजी बाजार में आगामी सप्ताह निवेशकों के लिए कई नए अवसर लेकर आ रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड समेत चार कंपनियां अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आ रही हैं। इन कंपनियों का मकसद कारोबार विस्तार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना है। दिसंबर के पहले सप्ताह में मोनोमार्क इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड और मातंगी रबर लिमिटेड पूंजी जुटाने के लिए अपना आईपीओ ला रही हैं। मोनोमार्क इंजीनियरिंग का आईपीओ 2 से 4 दिसंबर तक खुला रहेगा, जबकि मातंगी रबर का सार्वजनिक निर्गम 1 से 3 दिसंबर तक अभिदान के लिए उपलब्ध होगा। दोनों कंपनियां अपने आईपीओ खुलने से ठीक पहले एंकर निवेशकों के लिए बोली आयोजित करेंगी, मातंगी रबर के लिए 30 नवंबर को और मोनोमार्क इंजीनियरिंग के लिए 1 दिसंबर को। इसके अतिरिक्त नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी दो अन्य आईपीओ बाजार में आएंगे। खाद्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) लिमिटेड का आईपीओ 26 नवंबर को लान्च होगा।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से व्यापार, निवेश के नए अवसर खुलेंगे: जर्मन राज्य प्रमुख



नई दिल्ली। जर्मनी के लोअर सैक्सोनी राज्य के प्रमुख ओलाफ लीस ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों पक्षों के बीच निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर खोलेगा। इस समझौते पर दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जबकि इसकी बातचीत जनवरी में पूरी हो चुकी है। भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा पर आए लीस ने नई दिल्ली स्थित जर्मनी दूतावास में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एफटीए हमारे देशों के बीच अधिक निवेश, अधिक व्यापार और अधिक कारोबार के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल के अंत तक एफटीए को लेकर कोई समाधान निकल आएगा। करीब 60 राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लीस ने बताया कि यह समझौता भारत में निवेश करने की इच्छुक उनकी राज्य की कंपनियों के साथ ही जर्मनी में अवसर तलाश रहे भारतीय व्यवसायों को भी लाभ पहुंचाएगा। लीस अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली, पुणे और मुंबई में बैठकें करेंगे।

निजी क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि, पहली छमाही में 26.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा : सीआईआई

नई दिल्ली

देश में निजी क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों में तेजी आई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की घोषणाएं 26.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 58.5 प्रतिशत अधिक हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने इस पर कहा कि सरकार के नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और नियामकीय व्यवस्था में बदलावों से निजी निवेश के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। उद्योग जगत विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने के लिए निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को प्रतिबद्ध है। सीआईआई के अनुसार, उसके निजी निवेश बैरोमीटर के दूसरे संस्करण में सामने आया है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में निजी क्षेत्र की परियोजना घोषणाएं वित्त वर्ष 2017 से 2025 की पहली छमाहियों के औसत से 4.4 गुना अधिक रहीं। कुल परियोजना घोषणाओं में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी भी एक साल पहले के 74.2 प्रतिशत से बढ़कर 86.2 प्रतिशत हो गई।

सीआईआई अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने कहा कि सरकार ने लगातार नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और नियामकीय ढांचे में सुधार के जरिए निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद नीतियों में निरंतरता से उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है और दीर्घकालिक निवेश के फैसलों को लेकर स्पष्टता आई है। उन्होंने कहा कि निवेश घोषणाओं और वास्तविक पूंजी निर्माण, दोनों में इसके सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं।

बैरोमीटर के अनुसार, करीब 1,800 सूचीबद्ध निजी कंपनियों का सकल पूंजी निर्माण वित्त वर्ष 2025-26 में 12.4 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.6 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2017 से 2021 के दौरान यह औसतन 2.2 प्रतिशत था। समान कंपनियों के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 में निवेश में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा 54 प्रतिशत कंपनियों ने अपने स्थायी निवेश की दर बढ़ाई, जबकि करीब तीन-चौथाई कंपनियों ने अपनी शुद्ध उत्पादक क्षमता में इजाफा किया। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान निजी क्षेत्र की पूरी हुई परियोजनाओं का मूल्य 1.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2017 के बाद इस अवधि का सबसे अधिक स्तर है। मुकुंदन ने कहा कि भारतीय उद्योग विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। कंपनियों की मजबूत वित्तीय स्थिति और देश की आर्थिक संभावनाओं में बढ़ते भरोसे से इस निवेश को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब उद्योग जगत की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मुकुंदन ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग जगत को टीम भारत के रूप में मिलकर काम करना होगा। इसके लिए निवेश और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी, गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सृजन, उत्पादकता बढ़ाना, विनिर्माण और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना तथा अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास, निर्यात विस्तार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ाव भी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इसके साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय कंपनियां विकसित करने और विकास प्रक्रिया में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। बैरोमीटर में निवेश के बदलते स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 8.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा हुई, जो इसके ऐतिहासिक औसत से 3.2 गुना अधिक है। बिजली क्षेत्र में 7.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गई, जो ऐतिहासिक औसत से 5.1 गुना है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परियोजना घोषणाएं करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये रहीं। इनमें मुख्य रूप से डेटा सेंटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़ा बुनियादी ढांचा शामिल है। पिछले वर्ष की समान अवधि में इस क्षेत्र में 70 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा हुई थी। सीआईआई ने वित्तीय बाजारों के आधुनिकीकरण और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। संगठन के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सहित नियामकों की परामर्श आधारित कार्यप्रणाली से पूंजी बाजार अधिक मजबूत और सक्षम बने हैं। दीर्घकालिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों की सुरक्षा, बाजार की पारदर्शिता, नियामकीय स्थिरता और अनुपालन की उचित व्यवस्था जरूरी है।

ऑडी इंडिया वाहनों की कीमतों में दो फीसदी तक करेगा इजाफा, नई कीमतें एक जनवरी से होंगी लागू



नई दिल्ली

जर्मन लग्जरी कार निर्माता आडी ने मंगलवार को भारत में अपने सभी माडलों की कीमतों में दो फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतें एक जनवरी, 2027 से लागू होंगी। आडी ने एक बयान में कहा कि वह बढ़ती इनपुट लागत की भरपाई के लिए भारत में अपने सभी माडलों की एक्स-शोरूम कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने कहा कि संशोधित कीमतें 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगी। जर्मनी की लग्जरी कार विनिर्माता आडी ने कहा कि यह ताजा बढ़ोतरी 2026 में आडी इंडिया का दूसरा मूल्य संशोधन है।

वाहन विनिर्माता कंपनी ने इससे पहले इस साल एक अप्रैल से अपने सभी माडलों की कीमतों में दो फीसदी तक की वृद्धि की थी। कंपनी ने कहा कि यह मूल्य संशोधन इसके सभी माडलों पर लागू होगा।

वहीं, आडी इंडिया के ब्रांड निदेशक बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, कच्चे माल की बढ़ती हुई लागत के चलते हम कीमतों में दो फीसदी तक का संशोधन कर रहे हैं। हमारे कारोबार की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह समायोजन जरूरी है। हमने इस संशोधन को यथासंभव सीमित रखा है। आडी इंडिया के मौजूदा पोर्टफोलियो में कई लग्जरी कारें हैं, जिसमें सेडान और एसयूवी शामिल हैं। इनमें ए4 और ए6 एसयूवी, तथा क्यू3, क्यू5, क्यू7 और क्यू8 एसयूवी हैं। कंपनी की परफारमेंस-ओरिएंटेड (बेहतर प्रदर्शन वाली) गाड़ियों में एक्यू8 और आरएस क्यू8 भी हैं। कंपनी भारत में क्यू3 भी बेचती है। इसका लेटेस्ट जनरेशन अक्टूबर 2026 में लान्च किया गया था और इसे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित वोक्सवैगन ग्रुप की फैसिलिटी में असेंबल किया जाता है।

जेएसडब्ल्यू मोटर्स और एआरएआई में नए ऊर्जा वाहन विकास हेतु समझौता



नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू समूह की यात्री वाहन इकाई, जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने नए ऊर्जा वाहनों (एनईवी) के संयुक्त विकास, परीक्षण और स्थानीयकरण के लिए आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य वाहनों और उनकी प्रणालियों के विकास के लिए मजबूत तकनीकी आधार तैयार करना, परीक्षण एवं नियामकीय तैयारियों को बेहतर बनाना है। कंपनी विशेष रूप से भारतीय परिचालन स्थितियों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना चाहती है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल वाहन बनाना नहीं, बल्कि मजबूत स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमताओं वाली विश्वस्तरीय भारतीय वाहन कंपनी बनाना है। उन्होंने जोर दिया कि यह साझेदारी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अगली पीढ़ी के परिवहन समाधान विकसित करने में तेजी लाएगी। जेएसडब्ल्यू मोटर्स 3 दिसंबर को अपनी पहली एसयूवी के साथ भारतीय यात्री वाहन बाजार में प्रवेश करेगी, जिसका विनिर्माण महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित संयंत्र में किया जाएगा।

सेबी ने आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम पर लगाई रोक, निवेशकों को आगाह किया

बाजार मध्यस्थों को प्रचार-प्रसार से रोका, निवेशकों को अनौपचारिक सौदों से बचने की सलाह

नई दिल्ली

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) के आंकड़ों के प्रकाशन और प्रचार-प्रसार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियामक ने बाजार मध्यस्थों और अन्य प्रतिभागियों को इस तरह की गतिविधियों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही सेबी ने निवेशकों को जीएमपी को संभावित लिस्टिंग मूल्य या अपेक्षित रिटर्न का संकेतक न मानने की सख्त चेतावनी दी है। सेबी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि जीएमपी उन अनौपचारिक और अपुष्ट कीमतों को दर्शाता है जिन पर किसी कंपनी के शेयर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से पहले कारोबार किए जाने का दावा किया जाता है। ये सौदे मान्यता-प्राप्त शेयर बाजारों के दायरे से बाहर होते हैं, जिस पर कोई नियामकीय निगरानी नहीं होती और न ही इनमें निवेशकों को कोई सुरक्षा या सौदे के निपटान की गारंटी मिलती है।

नियामक ने पाया कि जीएमपी के आंकड़े



वेबसाइटों, डिजिटल मंचों, समाचार पत्रों और यहां तक कि सेबी में पंजीकृत कुछ मध्यस्थों द्वारा भी व्यापक रूप से प्रकाशित किए जा रहे थे। नियामक ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रीमियम के आंकड़ों का प्रकाशन निवेशकों के हितों के लिए नुकसानदेह है और प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता व जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत है। सेबी ने अपने सभी पंजीकृत मध्यस्थों और बाजार प्रतिभागियों को अपनी वेबसाइट, डिजिटल मंचों, ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया सहित किसी भी संचार माध्यम पर आईपीओ के जीएमपी के आंकड़े प्रकाशित, प्रदर्शित या प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया है। निवेशकों को भी आगाह किया गया है कि वे जीएमपी को शेयरों के सूचीबद्ध होने के संभावित भाव या अपेक्षित रिटर्न का संकेतक न मानें। उन्हें जीएमपी से जुड़े किसी भी अनौपचारिक सौदे से बचने और आईपीओ में केवल सेबी में पंजीकृत मध्यस्थों व अधिकृत मंचों के जरिये ही निवेश करने की सलाह दी गई है। सेबी ने साफ किया कि जीएमपी से जुड़े सौदों में विवाद होने पर निवेशकों को नियामक के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण और विवाद समाधान व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जिसमें सेबी या शेयर बाजारों की निवेशक सुरक्षा व शिकायत निवारण प्रणाली शामिल नहीं होगी।

टाटा स्टील-एपीएल अपोलो मेगा डील: शेयर लुढ़के, कर्ज बढ़ा, भविष्य की संभावनाएं

नई दिल्ली

देश के स्टील सेक्टर में एक बड़ी हलचल के तहत टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बीच लगभग 28,000 करोड़ रुपये की एक मेगा डील चर्चा में है। इस सौदे के तहत टाटा स्टील, एपीएल अपोलो में 52.6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है, साथ ही अपना ट्यूब और कलर कोटेड कारोबार एपीएल अपोलो को बेचेगी।

इस खबर से निवेशकों में चिंता बढ़ गई, जिसके चलते 23 नवंबर, को टाटा स्टील के शेयर 8 फीसदी और एपीएल अपोलो के शेयर 21 फीसदी से अधिक गिर गए। यह मेगा डील दोनों कंपनियों के कारोबार में बड़ा बदलाव लाने वाली है। टाटा स्टील एपीएल अपोलो में 52.6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अधिकतम 32,266 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है।

इसके समानांतर, वह अपना ट्यूब कारोबार

28,000 करोड़ के सौदे में टाटा स्टील चुकाएगी ऊंची कीमत

और टाटा स्टील कलर्स का पूरा कारोबार 28,000 करोड़ रुपये में एपीएल अपोलो को बेचेगी। हालांकि, इस सौदे की खबर के साथ ही शुरुआती खर्च, बढ़ते कर्ज और कमाई पर दबाव की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी।

जानकारों का मानना है कि टाटा स्टील एपीएल अपोलो की हिस्सेदारी के लिए काफी ऊंची कीमत चुका रही है, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। डील के बाद टाटा स्टील के कर्ज का बोझ बढ़ने का अनुमान है। सितंबर 2026 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट डेट 91,400 करोड़ रुपये था, जो सौदा पूरा होने के बाद लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

यानी, कंपनी पर करीब 28,600 करोड़



रुपये का अतिरिक्त कर्ज चढ़ेगा, जिससे कर्ज घटाने की रफ्तार धीमी हो सकती है। शुरुआती दो-तीन साल तक इस डील का टाटा स्टील की प्रति शेयर कमाई पर नकारात्मक असर दिखने की आशंका है। इसके बावजूद, इस सौदे से टाटा स्टील को एपीएल अपोलो का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड और देशव्यापी कारोबार मिलेगा, जिससे भविष्य में स्टील पाइप और कलर कोटेड प्रोडक्ट के बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। दोनों कंपनियों की संयुक्त उत्पादन क्षमता वर्तमान में 75 लाख टन सालाना है, जिसे अगले 5-6 सालों में बढ़ाकर 1.55 करोड़ टन सालाना करने की योजना है।

प्रबंधन को उम्मीद है कि नए कारोबार से 4-5 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपये के एबिटा की क्षमता बन सकती है और साढ़े तीन साल में ईपीएस पर सकारात्मक असर दिखेगा। विशेषज्ञों ने टाटा स्टील के शेयर पर खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखते हुए 219 रुपये का अपसाइड टारगेट दिया है, यह मानते हुए कि डील महंगी जरूर है, पर जुड़े जोखिमों का काफी असर शेयर के भाव में पहले ही दिख चुका है।